हमारे ई-पेपर को पढ़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

हमारे दैनिक खबरों को डिजिटल माध्यम में देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

ठीहा छत्तीसगढ़

समस्या से समाधान तक




वर्ष-01 | अंक-02 | पाक्षिक | 16 से 31 अगस्त 2026 | मूल्य : 20 | पृष्ठ- 12

# ढाई साल के कामकाज का हिसाब - किताब

## उप-मुख्यमंत्री अरुण साव से विशेष बातचीत

छत्तीसगढ़ सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश में विकास, रोजगार, सड़क, पेयजल, शिक्षा, खेल और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार के कामकाज पर चर्चा तेज है। इसी सिलसिले में ठीहा छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग सहित महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे अरुण साव से विशेष बातचीत की।

**ठीहा छत्तीसगढ़ के संपादक देवानंद साहू और सह संपादक राकेश निर्मलकर ने इस विशेष इंटरव्यू में उप मुख्यमंत्री अरुण साव से उनके विभागों से जुड़े कामकाज के साथ-साथ सरकार के ढाई साल के कार्यकाल का विस्तृत लेखा-जोखा जाना।**

***सवाल: आप जो गुलाबी रंग का गमछा पहनते हैं, क्या वह भाभी जी की पसंद है या कोई विशेष कारण है? क्या भाजपा का भगवा छोड़कर इस गमछे को चुनने का कोई राजनीतिक परिपेक्ष्य है?***

जवाब: यह गमछा उनकी खुद की प्रेरणा और बचपन की यादों से जुड़ा है। गाँव में रहते हुए हर कोई इसी प्रकार का सूती गमछा इस्तेमाल करता था क्योंकि यह बहुत नरम और बहुपयोगी होता है। मुँह पोंछने, नहाने, धूप से बचने और ओढ़ने तक के काम आने वाले इस गमछे को वे हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। इस गमछे को पहनने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यह विशुद्ध रूप से गाँव के गरीब और आम आदमी की पहचान है, जिसे उनके परिवार के बुजुर्ग भी पहनते थे। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें भगवा या अन्य गमछे पहनने से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों और छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जुड़े रहने के कारण वे इसे ही ज्यादा पसंद करते हैं।

***सवाल: वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित करने के बाद कांग्रेस के विरोध और बदलते रुख पर आप क्या कहेंगे?***

संसद में पारित कानून का पालन सभी को करना चाहिए। कांग्रेस के रवैये को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' हमारी आजादी का मूल मंत्र है। इसका विरोध करना केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति है। यह रवैया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, देश की 140 करोड़ जनता और भारतीय संविधान का घोर अपमान है।

***सवाल: सरकार के ढाई साल पूरे होने पर इसे आप कैसे देखते हैं?***

जवाब: 'मोदी की गारंटी' वाले वादे प्राथमिकता से पूरे किए जा रहे हैं। सरकार बनने के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, किसानों का धान 3100रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खाते में 1000रु. दिए जा रहे हैं। जनता का विश्वास भी चुनावों में साफ दिखाई दे रहा है।

***सवाल: युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के वादों पर अब तक क्या काम हुआ है?***

जवाब: विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, इंजिनियरिंग आदि में लगातार भर्तियां चल रही हैं। इसके अलावा राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत नए उद्योगों को रोजगार सृजन के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

***सवाल: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें लोग हाथ से सड़क का डामर उखाड़ते हुए दिखाई देते हैं। गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?***

जवाब: नई बनी सड़कों के डामर को मजबूत होने में समय लगता है। निगरानी के लिए उच्च अधिकारियों की समितियां बनाई गई हैं और केंद्र सरकार की एजेंसियों से थर्ड पार्टी जांच की व्यवस्था की जा रही है। गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

***सवाल: जब किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो वे अक्सर किसी अन्य फर्म के नाम से वापस आ जाते हैं। ठेकेदारों पर सीधे कठोर कार्रवाई करने का कोई विशेष प्रावधान लाया गया है?***

जवाब: वर्तमान में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत पुख्ता नहीं है, जिसके कारण ऐसी स्थिति संभव है। इस विषय पर संज्ञान लेंगे और इस खामी को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे ताकि इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

***सवाल: लोक निर्माण विभाग (PWD) सड़कों के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है ऐसा कहा जाता है, विभाग इस दिशा में कैसे काम कर रहा है?***

जवाब: कभी-कभी प्रशासकीय प्रक्रियाओं में समय लग जाता है, लेकिन विभाग पूरी तरह सजग है। उन्होंने बताया कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिए एक नई योजना लाई गई है, जिसमें ठेकेदारों को 5 साल के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही, तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है।

***सवाल: स्काई वॉक प्रोजेक्ट 2017-18 में शुरू हुआ था, जो बीच में 5 साल तक रुका रहा और अभी भी निर्माण अधीन है। कुछ लोग इस परियोजना को 'जिद' कहते हैं, तो कुछ इसे 'मजबूरी' या 'विकास' का नाम देते हैं, तो इस पर उनका क्या कहना है और यह कब तक पूरा हो जाएगा?***

जवाब- कांग्रेस पार्टी की जिद के कारण ही यह 5 साल तक रुका रहा, जबकि उन्होंने स्वयं इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई थी और अंत में इसे बनाने के पक्ष में निर्णय लिया था। सरकार का काफी पैसा इसमें पहले ही लग चुका था, इसलिए इसे बीच में रोकना उचित नहीं था। सरकार अब इसे तेज गति से पूरा कर रही है और निर्धारित समय में इसे पूरा करने की योजना है

***सवाल: जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनने के बाद भी पानी नहीं मिलने की शिकायतें क्यों आ रही हैं?***

जवाब: निर्माणाधीन मकान में खिड़की-दरवाजे अंत में लगते हैं, वैसे ही कई जगह पाइपलाइन और टंकी का काम अभी प्रक्रिया में है। पिछली सरकार की लापरवाही को सुधारते हुए 29,000 में से लगभग 12,000 योजनाओं का काम पूरा किया जा चुका है। लक्ष्य के अनुसार 2028 तक सभी घरों में नल और जल पहुँच जाएगा।

***सवाल : हर साल पता होता है कि बारिश होगी, इसके बावजूद हर बार बारिश होने पर शहर डूब क्यों जाते हैं? रास्ते बंद हो जाते हैं, पुल पानी से भर जाते हैं और शहर अपने आप में कटा-कटा सा महसूस होने लगता है।***

जवाब शहरों का विकास बिना किसी ठोस योजना (बेतरतीब) के हुआ है। पहले से पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से पुरानी बस्तियों और मोहल्लों में पानी भर जाता है। लोग नालियों और नालों में कचरा डाल देते हैं या उन पर बेजा कब्जा कर लेते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और जलभराव होता है। जनता से अपील है कि वे नालियों में कचरा न डालें और पानी का बहाव रोकने वाला कोई काम न करें। यह समस्या जन-सहयोग के बिना पूरी तरह से हल नहीं हो सकती।

***सवाल: साहू समाज में धर्मांतरण और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?***

जवाब: पिछली कांग्रेस सरकार के समय यह खुलेआम हो रहा था। साहू समाज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है, इसलिए वहां इसे लेकर गहरी चिंता है और वे घर-घर जाकर जनजागरण अभियान चला रहे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रलोभन या दबाव से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बना दिए हैं।

***सवाल: चुनाव के समय मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चर्चा में रहने के बाद भी जिम्मेदारी न मिलने पर कोई मलाल है?***

जवाब: रत्ती भर भी मलाल नहीं है। खुद को गाँव का एक साधारण कार्यकर्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और अब उपमुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है। वे किसी पद की लालसा किए बिना सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं।

***सवाल: खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या योजना है?***

जवाब: पिछली सरकार द्वारा बंद की गई 'खेल अलंकरण' योजना को पुनः शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में नेशनल ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया और हॉकी-कबड्डी लीग जैसे बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही, स्कूलों में तीसरी-चौथी कक्षा से ही 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम के जरिए बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने की योजना पर भी तेज़ी से काम चल रहा है।

# आपदा में प्रबंधन विभाग!

### न मुसीबत से निकलने का रास्ता, न सही उपकरण - फिर ये विभाग किस दिन के लिए है?

रायपुर के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर प्वाइंट में एक युवक पानी में डूबा रहा, और परिवार कलेजा थामे किनारे पर बैठा रहा। जिस विभाग का काम है ऐसी घड़ी में सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे सक्षम होकर पहुंचना - वह विभाग दिनों तक बस "संसाधन जुटाने" में ही लगा रहा। आखिरकार जो मिला, वह जीवन नहीं, एक निष्प्राण देह थी - वह भी तब, जब पानी ने खुद उसे ऊपर धकेल दिया। सवाल यह नहीं कि आदिल की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि जिस विभाग का नाम ही "आपदा प्रबंधन" है, वह खुद किस आपदा में जी रहा है कि एक शव तक नहीं ढूंढ़ पाया।

### हाईटेक विभाग, लो-टेक हकीकत

कागज़ों में यह विभाग खुद को अत्याधुनिक, हाईटेक और पूरी तरह तैयार बताता है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत यह है कि रायपुर जैसी राजधानी की टीम के पास अपना अंडरवाटर कैमरा तक नहीं था - दूसरे जिलों से मंगवाना पड़ा। जो कैमरा और जो स्कूबा ट्रेनिंग उपलब्ध थी, वह खदान की असली गहराई के आगे बौनी साबित हुई। यानी जिस चुनौती से जूझना था, उसके सामने विभाग के संसाधन कहीं टिकते ही नहीं। यह किसी एक दिन की चूक नहीं, यह वर्षों की लापरवाही का नतीजा है - ऐसी लापरवाही जो हर हादसे के बाद भाषण बनकर उभरती है और अगले हादसे तक भुला दी जाती है।

### सालों पुराना खतरा, एक चेतावनी बोर्ड

यह पहली बार नहीं हुआ। इसी ब्लू वाटर खदान में पहले भी कई जानें जा चुकी हैं। और प्रशासन ने इतने बड़े ख़तरे को रोकने के लिए जो सबसे ठोस कदम उठाया, वह था - एक चेतावनी बोर्ड। एक बोर्ड, जो न किसी को खदान में जाने से रोक पाया, न किसी की जान बचा पाया। पंचायत ने बार-बार खदान की चारदीवारी और बैरिकेडिंग की मांग की, फाइलें बनीं, आवेदन दिए गए - नतीजा सिफर। जब तक हादसा नहीं होता, तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती; और हादसे के बाद भी फाइल उतनी ही धीमी चलती है जितनी रेस्क्यू टीम की नाव।

### अफसर तब पहुंचे, जब जनता ने हंगामा किया

सबसे शर्मनाक तस्वीर यह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोक दिया गया, और अफसर मौके पर तब पहुंचे जब गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया और कलेक्टर तक शिकायत पहुंची। यानी संवेदनशीलता किसी विभागीय ज़िम्मेदारी से नहीं, जनता के दबाव से आई। जिस सरकारी तंत्र को खुद आगे बढ़कर परिवार का सहारा बनना चाहिए था, वह तमाशबीन बना खड़ा रहा - और हरकत में तब आया जब सड़क पर नारे गूंजे।

### प्रचार की गहराई, काम की उथलापन

यही वह विभाग है जो अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग और विज्ञापनों पर खर्च करने में पीछे नहीं रहता। मॉक ड्रिल की तस्वीरें, "आपदा तैयारी" के बड़े-बड़े दावे - यह सब तब तक चमकते हैं जब तक असली आपदा दरवाज़े पर दस्तक न दे। जिस दिन असली परीक्षा आई, विभाग की "तैयारी" खदान की गहराई में कहीं डूबकर रह गई। विडंबना यह है कि जिस विभाग का पूरा अस्तित्व ही आपदा से निपटने के लिए है, वही आपदा के सामने सबसे बेबस नज़र आया - और वह भी तब जब मौके पर अफसरों, नेताओं और कर्मचारियों की भीड़ कम नहीं थी, कमी सिर्फ काम की थी।

### सवाल अब भी वहीं खड़ा है

आदिल के मां-बाप के लिए अब कोई जवाब मायने नहीं रखता - उनका बेटा नहीं लौटेगा। लेकिन बाकी परिवारों के लिए, जो इसी खदान के आसपास रहते हैं, यह सवाल जिंदा रहना चाहिए: क्या अगली बार भी विभाग को पड़ोसी जिले से कैमरा उधार मांगना पड़ेगा? क्या अगली मौत के बाद भी सिर्फ एक और चेतावनी बोर्ड लगा दिया जाएगा? जनता हंगामा करेगी, तब कलेक्टर पहुंचेंगे - या इस बार पहले से कोई सबक लिया जाएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक "आपदा प्रबंधन" सिर्फ एक नाम है - एक ऐसा विभाग जिसकी सबसे बड़ी आपदा वह खुद है।

- संपादकीय टिप्पणी
**देवानन्द साहू**

---

# भाजपा के आईटी सेल में बड़ा बदलाव

## मालवीय के सफर पर विराम, दीपक म्हस्के के सामने जेन ज़ी की चुनौती

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल में बड़ा बदलाव करते हुए लंबे समय से इसकी कमान संभाल रहे अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को नई जिम्मेदारी सौंपी है। करीब 11 वर्षों तक भाजपा के डिजिटल मोर्चे को संभालने वाले मालवीय का स्थानांतरण ऐसे समय हुआ है, जब सोशल मीडिया की दुनिया तेजी से बदल रही है और युवा वर्ग, खासकर जेन ज़ी, राजनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।

### मालवीय का लंबा डिजिटल सफर

अमित मालवीय ने वर्ष 2015 से भाजपा के आईटी और सोशल मीडिया संगठन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में भाजपा ने सोशल मीडिया को राजनीतिक संचार के एक प्रभावी हथियार के रूप में स्थापित किया। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल मंचों के माध्यम से पार्टी के संदेश को तेजी से लोगों तक पहुंचाने की रणनीति को विस्तार मिला।

मालवीय के नेतृत्व में भाजपा का आईटी सेल चुनावी अभियानों, विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव और पार्टी की नीतियों को डिजिटल मंचों पर पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय रहा। हालांकि अब सोशल मीडिया का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। युवा दर्शक पारंपरिक पोस्ट और लंबे राजनीतिक संदेशों के बजाय छोटे वीडियो, रील्स और तेजी से वायरल होने वाले कंटेंट की ओर अधिक आकर्षित हैं।

### कौन हैं दीपक म्हस्के?

अमित मालवीय के बाद भाजपा ने दीपक म्हस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ से जुड़े म्हस्के की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अलग तरह की है। वे रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और कृषि तथा बागवानी क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। उन्हें आंकड़ों और डेटा विश्लेषण की समझ रखने वाला चेहरा माना जाता है।

नई जिम्मेदारी संभालने के बाद म्हस्के ने संकेत दिया है कि उनकी प्राथमिकताओं में जेन ज़ी तक पहुंच बनाना और इंस्टाग्राम रील्स जैसे मंचों पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना महत्वपूर्ण होगा। यह भाजपा की डिजिटल रणनीति में संभावित बड़े बदलाव का संकेत है।

### मालवीय को हटाने का कारण क्या?

भाजपा ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि अमित मालवीय को जेन ज़ी से जुड़े विरोध प्रदर्शनों या किसी एक घटना के कारण हटाया गया है। इसलिए इसे सीधे तौर पर किसी एक कारण से जोड़ना उचित नहीं होगा।

लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम और बदलाव के समय को देखते हुए कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालिया जेन ज़ी प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील्स और छोटे वीडियो बेहद तेजी से वायरल हुए। भाजपा के पारंपरिक डिजिटल नैरेटिव के सामने युवा वर्ग के बीच नए तरह के कंटेंट ने चुनौती खड़ी की। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी और संवाद को अधिक प्रभावी बनाना पड़ा।

यही बदलाव भाजपा के लिए संकेत है कि युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल रणनीति को नई भाषा और नए मंचों के अनुरूप ढालना जरूरी हो गया है।

### बदलाव के पीछे बड़ी रणनीति

दीपक म्हस्के की नियुक्ति को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा अब केवल राजनीतिक संदेश जारी करने के बजाय यह समझने पर जोर दे सकती है कि युवा क्या देख रहे हैं, किस तरह की सामग्री साझा कर रहे हैं और कौन-सा नैरेटिव तेजी से फैल रहा है।

जेन ज़ी इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय है। ऐसे में रील्स, छोटे वीडियो, प्रभावी दृश्य सामग्री और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली डिजिटल टीम आने वाले समय में भाजपा की प्राथमिकता बन सकती है।

मालवीय के दौर में भाजपा ने डिजिटल राजनीति की मजबूत नींव तैयार की। अब म्हस्के के सामने चुनौती उस मॉडल को नई पीढ़ी की डिजिटल आदतों के अनुरूप बदलने की है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव केवल आईटी सेल का संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि भाजपा की युवा और डिजिटल राजनीति की नई दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है।

Printed by Published by DEVANAND on behalf of DEVANAND, printed at A.R. Printers, B-1, in front of raymond showroom, shivam market, pandri and published at 875, in front of mahaveer cutpiece, Bajnathpara, Raipur. ZIP - 492001. Editor- DEVANAND, Mobile No. - 99269 33309.

# नक्सलवाद से स्वतंत्रता का उद्घोष: कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर लहराया तिरंगा

## बस्तर तिरंगा यात्रा का समापन उस गढ़ पर, जहां कभी तिरंगा फहराना भी था नामुमकिन

• **राकेश निर्मलकर**, संवाददाता, रायपुर

रायपुर/बीजापुर। आज़ादी के अमृतकाल में बस्तर के जिस कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को नक्सलियों का सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वहीं अब राष्ट्रीय ध्वज पूरे गर्व के साथ लहरा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में निकाली गई "बस्तर तिरंगा यात्रा" तीन दिनों के सफर के बाद कर्रेगुट्टा पहुंचकर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह दृश्य केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दशकों से हिंसा और भय के साये में जी रहे बस्तरवासियों के लिए स्वतंत्रता के एक नए अध्याय की शुरुआत है।

यह तिरंगा यात्रा महज एक प्रशासनिक या राजनीतिक आयोजन भर नहीं है - यह बस्तर की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। जिस भूभाग में वर्षों तक बंदूक की गूंज के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था, वहां आज तिरंगे के साथ बाइकों का काफिला निकलना यह दर्शाता है कि नक्सलवाद की जड़ें अब कमजोर पड़ रही हैं और आम जनमानस में सुरक्षा और विश्वास की भावना लौट रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वयं बाइक पर सवार होकर, बिना किसी दिखावे के, उन्हीं रास्तों से यात्रा की जो कभी सुरक्षाबलों के लिए भी चुनौती हुआ करते थे। यह नेतृत्व की वह मिसाल है जो केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ज़मीन पर उतरकर दिखाई गई। कर्रेगुट्टा जैसे इलाके तक पहुंचना और वहां तिरंगा फहराना, प्रदेश सरकार की नक्सल विरोधी रणनीति की सफलता का स्पष्ट संकेत है।

बस्तर की यह यात्रा आने वाले समय के लिए एक संदेश भी है - विकास, शांति और तिरंगे का सम्मान अब बस्तर के हर कोने तक पहुंचेगा। जो धरती वर्षों तक भय और हिंसा की पहचान बनी रही, वह अब स्वतंत्रता और नई सुबह के उद्घोष की गवाह बन रही है।

### **नारायणपुर से कर्रेगुट्टा तक:** 600 किलोमीटर का साहसिक सफर

यात्रा की शुरुआत नारायणपुर से हुई, जहां से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वयं बाइक चलाते हुए तिरंगा थामकर नेतृत्व किया। स्थानीय समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। पहले दिन यह यात्रा मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसुर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। दूसरे दिन यात्रा सुकमा और बीजापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से गुजरी।

तीसरे और अंतिम दिन 14 अगस्त को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने बीजापुर से आवापल्ली, गलगम, उसूर, नंबी, ताड़पाला होते हुए अपनी यात्रा को कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर ध्वजारोहण के साथ पूर्ण किया। नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर - इन पांच जिलों से गुजरते हुए मंत्री द्वय ने बाइक पर लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय की।

### "बिना डर के खड़े होने का सौभाग्य" - वन मंत्री केदार कश्यप

कर्रेगुट्टा पहुंचने पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कुछ समय पहले तक इस पहाड़ी तक पहुंच पाना भी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन आज बिना किसी भय के इस स्थान पर खड़ा होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनके शब्दों में इस पूरे सफर की गहराई झलकती है - यह पहाड़ी वर्षों तक नक्सली गतिविधियों का केंद्र रही, जहां सुरक्षाबलों के लिए भी पहुंचना आसान नहीं था।

वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कर्रेगुट्टा को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ बताते हुए कहा कि आज उसी पहाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज बिना किसी डर के फहराया जा रहा है। सांसद महेश कश्यप ने भी इस अवसर को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज़ादी के करीब आठ दशक बाद पहली बार इन क्षेत्रों में तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहरा रहा है।

# संगठन में जगह मिली सत्ता में हिस्सेदारी कब ?

• देवानंद, संपादक

## संगठन में जगह मिली, सत्ता में हिस्सेदारी कब ?

छत्तीसगढ़ के हक और सम्मान का सवाल छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इस राज्य ने भाजपा को जो दिया है, उसका हिसाब लगाना मुश्किल नहीं। हर लोकसभा चुनाव में ग्यारह में से नौ-दस सीटें, लगातार भरोसा, लगातार समर्थन। बदले में राज्य को क्या मिला एक राज्यमंत्री का पद, जिसकी सीमाएं किसी से छिपी नहीं। न कैबिनेट रैंक, न वह असर जो नीति-निर्धारण की मेज पर बैठने से आता है। जो राज्य वनों, खनिजों और बिजली के दम पर देश के औद्योगिक इंजन को ईंधन देता है, वही राज्य दिल्ली के सत्ता-गलियारों में अपनी आवाज़ के लिए तरसता रह जाए यह विडंबना नहीं तो और क्या है?

## संख्या का गणित, सम्मान का सवाल

तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। मध्यप्रदेश, जिसकी सीटें छत्तीसगढ़ से ज़्यादा हैं, वहां से कैबिनेट और राज्यमंत्री दोनों स्तर पर मज़बूत नुमाइंदगी है। झारखंड, जो सीटों में छत्तीसगढ़ जैसा ही छोटा राज्य है, वहां भी कैबिनेट रैंक की मौजूदगी है। फिर छत्तीसगढ़ के हिस्से सिर्फ राज्यमंत्री का पद ही क्यों? क्या समर्थन की निरंतरता किसी राज्य की अनदेखी का लाइसेंस बन जाती है -"यह तो वैसे भी साथ देगा" वाली मानसिकता? अगर हां, तो यह उस लोकतांत्रिक सौदे के खिलाफ है जिसमें जनता का भरोसा सत्ता में हिस्सेदारी से चुकाया जाना चाहिए, नज़रअंदाज़गी से नहीं।

## संगठन की सीढ़ी, सरकार की दूरी

हाल में भाजपा की नई टीम में छत्तीसगढ़ से तीन चेहरों को जगह मिली - यह संगठनात्मक स्तर पर राज्य की मौजूदगी को दिखाता है। रूप कुमारी चौधरी, दीपक म्हस्के और डॉ. संदीप पाठक जैसे नाम यह भी बताते हैं कि पार्टी संगठन में छत्तीसगढ़ को नज़रअंदाज़ नहीं कर रही। लेकिन यहीं एक फर्क साफ उभरता है - संगठन में जगह और सरकार में हिस्सेदारी, दोनों अलग चीज़ें हैं। एक जगह चेहरे बदलते रहते हैं, दूसरी जगह नीति औरबजट तय होते हैं। छत्तीसगढ़ को पहली जगह में जितनीउदारता मिली है, दूसरी जगह उतनी ही कंजूसी बरती गई है।

## सवाल राजनीति का नहीं, अधिकार का है

यह सवाल किसी दल-विरोध से नहीं उठता — यह उस बुनियादी तर्क से उठता है कि जो राज्य संसाधन और समर्थन दोनों देता है, उसे नीति-निर्माण में भी उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ मूल के डॉ. संदीप पाठक का आप से भाजपा में आना और चुनावी साल का यह मौका, दोनों मिलकर एक स्वाभाविक अवसर बनाते हैं - कि पार्टी अब सिर्फ संगठन में नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी छत्तीसगढ़ को उसका वाजिब हक दे। सवाल विरोध का नहीं, स्वाभिमान और प्रतिनिधित्व का है।

# भूपेश बघेल के जन्मदिन पर दिखा शक्ति प्रदर्शन जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकती कांग्रेस और भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल का नाम उन नेताओं में शुमार है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छवि को मजबूत किया और प्रदेश की सियासत में ऐसा व्यक्तिगत जनाधार तैयार किया, जिसकी चर्चा सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आज भी होती है। उनके 65वें जन्मदिन पर जिस तरह भिलाई, पाटन और रायपुर में समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भूपेश बघेल की लोकप्रियता को राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता है?

23 अगस्त को भूपेश बघेल का जन्मदिन तीन अलग-अलग पड़ावों में खास राजनीतिक चर्चा का विषय बना। उन्होंने पहले भिलाई में जन्मदिन मनाया, इसके बाद पाटन पहुंचे और फिर रायपुर में समर्थकों से मुलाकात की। तीनों जगहों पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। भिलाई-3 स्थित उनके निवास से लेकर पाटन और फिर रायपुर के सिविल लाइन स्थित निवास तक पूरे दिन समर्थकों की आवाजाही बनी रही।

## पाटन में उमड़ा जनसैलाब, लोकप्रियता का दिखा अलग रंग

भूपेश बघेल का राजनीतिक प्रभाव उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन में हमेशा से मजबूत माना जाता रहा है। जन्मदिन के अवसर पर पाटन में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने उनके व्यक्तिगत जनाधार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया।

पाटन में करीब 11 हजार लोगों के भोजन करने की जानकारी सामने आई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना केवल जन्मदिन समारोह तक सीमित नहीं माना जा रहा। समर्थकों की मौजूदगी और उत्साह ने यह संकेत जरूर दिया कि पाटन में भूपेश बघेल की पकड़ और व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी भी काफी मजबूत है।

उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने नेता के प्रति जुड़ाव और समर्थन दिखाने का अवसर भी नजर आया।

## रायपुर में भीड़ इतनी कि मंत्रियों के काफिले का बदला रास्ता

भूपेश बघेल के जन्मदिन का सबसे ज्यादा राजनीतिक असर रायपुर में देखने को मिला। सिविल लाइन स्थित निवास के आसपास बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने से यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा। समर्थकों की भारी भीड़ के कारण प्रदेश के मंत्रियों के काफिले को अपना रास्ता बदलना पड़ा, यह घटनाक्रम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।

रायपुर में सुबह से लेकर देर तक समर्थकों का पहुंचना जारी रहा। दूर-दराज के इलाकों से आए कार्यकर्ता और समर्थक घंटों तक अपने नेता से मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। भीड़ का यह स्वरूप इस बात का संकेत जरूर देता है कि सत्ता में नहीं होने के बावजूद भूपेश बघेल के प्रति लोगों का व्यक्तिगत आकर्षण खत्म नहीं हुआ है।

## भीड़ सिर्फ जन्मदिन की बधाई थी या शक्ति प्रदर्शन?

राजनीति में किसी नेता के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ को हमेशा केवल शुभकामना देने वालों की संख्या के रूप में नहीं देखा जाता। खासकर तब, जब नेता सत्ता में न हो और उसके बावजूद अलग-अलग शहरों में हजारों लोग जुटें।

भिलाई से पाटन और फिर रायपुर तक जिस तरह समर्थकों की मौजूदगी दिखाई दी, उसे भूपेश बघेल के राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हालांकि जन्मदिन पर जुटी भीड़ को सीधे चुनावी समर्थन का पैमाना मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस भीड़ ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक राजनीतिक संदेश छोड़ा है।

## कांग्रेस के कई दिग्गज नहीं पहुंचे, फिर भी कम नहीं हुआ उत्साह

इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी। कांग्रेस के भीतर समय-समय पर गुटबाजी और आपसी मतभेद की चर्चाएं सामने आती रही हैं।

ऐसे में कुछ बड़े नेताओं और विधायकों का जन्मदिन कार्यक्रमों से दूर रहना अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जाने का कारण बना। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल से मुलाकात करने पहुंचे और समर्थकों की बड़ी संख्या पूरे दिन उनके साथ खड़ी रही।

यही विरोधाभास छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है-संगठन के भीतर चाहे जितनी राजनीतिक खींचतान की चर्चा हो, भूपेश बघेल का व्यक्तिगत जनाधार अपनी जगह दिखाई देता है।

## भाजपा के लिए भी क्यों अहम हैं भूपेश बघेल?

भाजपा सरकार के करीब ढाई साल पूरे हो चुके हैं और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगभग ढाई साल का समय बाकी है। आने वाले समय में सरकार अपने कामकाज को जनता के बीच ले जाएगी, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी।

इस राजनीतिक मुकाबले में भूपेश बघेल जैसे चेहरे को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। भाजपा लगातार भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल को राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। लेकिन राजनीति का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जिस नेता पर विपक्ष लगातार हमला करता है, वह अक्सर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना रहता है।

भूपेश बघेल आज सत्ता में नहीं हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर उमड़ी भीड़ यह जरूर बताती है कि उनका राजनीतिक कद केवल मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं था।

## 2028 के लिए क्या संकेत छोड़ गया जन्मदिन?

छत्तीसगढ़ में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना है। अभी चुनाव में काफी समय बाकी है और इस समय किसी भी नेता की भीड़ को सीधे चुनावी परिणाम से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीति में संकेतों का अपना महत्व होता है।

भिलाई में शुरुआत, पाटन में जनसैलाब और रायपुर में समर्थकों की भारी मौजूदगी-इन तीनों तस्वीरों ने भूपेश बघेल की राजनीतिक सक्रियता और लोकप्रियता को फिर चर्चा में ला दिया है।

खासकर पाटन में उनकी लोकप्रियता का जो प्रदर्शन देखने को मिला, उसने यह स्पष्ट किया कि उनके अपने राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत पकड़ को नकारना आसान नहीं है।

## कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए संदेश

भूपेश बघेल के जन्मदिन पर जुटी भीड़ कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है और भाजपा के लिए भी।

कांग्रेस के लिए संदेश यह है कि संगठन के भीतर चाहे जितने मतभेद हों, भूपेश बघेल का व्यक्तिगत प्रभाव अभी भी बड़ा है। ऐसे जनाधार वाले नेता को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा।

वहीं भाजपा के लिए संदेश यह है कि सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष के ऐसे नेताओं के व्यक्तिगत जनाधार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले ढाई वर्षों में राजनीतिक समीकरण कई बार बदलेंगे और 2028 की लड़ाई में कौन सा चेहरा कितना प्रभावी होगा, यह समय के साथ स्पष्ट होगा।

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल के 65वें जन्मदिन ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तस्वीर साफ कर दी है-सत्ता से बाहर होने के बावजूद उनका राजनीतिक कद और व्यक्तिगत लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है।

भिलाई से पाटन और पाटन से रायपुर तक उमड़ी भीड़ ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है- क्या 2028 की राजनीति में भूपेश बघेल फिर से एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे?

इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उनके जन्मदिन पर दिखाई दिया जनसमर्थन इतना जरूर कहता है कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजरअंदाज करना कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए आसान नहीं होगा।

सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन मजबूत व्यक्तिगत जनाधार वाला नेता लंबे समय तक राजनीति में प्रासंगिक बना रहता है।

# सब्जी से लेकर राशन सब महंगा हो गया है

• **आरती बेनिया**, संवाददाता, रायपुर

रायपुर। राजधानी रायपुर के बाजारों में इन दिनों आम आदमी की जेब पर चौतरफा मार पड़ रही है। सुबह की चाय की चुस्की से लेकर रात के खाने की थाली तक, हर जरूरी चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। जो मध्यमवर्गीय परिवार आज से ठीक एक महीने पहले तक महीने का पूरा किराना और राशन 4 से 5 हजार रुपये में घर ले आता था, आज उसी राशन के लिए जेब से सात हजार रुपये से अधिक ढीले करने पड़ रहे हैं। त्योहारों के ठीक पहले बेलगाम हुई इस महंगाई ने रायपुर की गृहणियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

### एक महीने में ₹20 का उछाल

राशन की बात करें तो इस महीने सबसे बड़ा झटका शक्कर ने दिया है। पिछले सिर्फ चार हफ्तों के भीतर रायपुर के चिल्हर मार्केट में शक्कर के दाम करीब 30 से 35 फीसदी तक बढ़ चुके हैं। शक्कर महंगी होने के चलते जब लोगों ने विकल्प के रूप में गुड़ का रुख किया, तो भारी डिमांड को देखते हुए थोक व्यापारियों ने गुड़ के दाम भी 15% तक बढ़ा दिए। चाय से लेकर त्योहारों की मिठाइयों तक का स्वाद अब कड़वा होने लगा है।

### प्याज और टमाटर दिखा रहे आंखें, हरी मिर्च भी हुई तीखी

सब्जी मंडी का हाल तो और भी ज्यादा बदतर है। बाजार में झोला लेकर जाने वाले आम नागरिकों के पसीने छूट रहे हैं। मानसून की मार और बाहरी राज्यों से आने वाली खेप प्रभावित होने के कारण रायपुर के डूमरतराई और शास्त्री बाजार में सब्जियों की कीमतें आग उगल रही हैं। सबसे ज्यादा असर रोजाना इस्तेमाल होने वाले आलू और प्याज पर पड़ा है। वहीं, जो धनिया पत्ती पहले दुकानदार सब्जी के साथ मुफ्त में डाल दिया करते थे, आज उसे खरीदने के लिए भी मोल-तौल करना पड़ रहा है।

### धान के कटोरे में चावल और तेल भी बेलगाम

हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन खुद रायपुर की जनता को अब महंगा चावल खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रोजाना के खाने में इस्तेमाल होने वाले मशहूर एचएमटी और महामाया जैसी चावल की किस्मों पर 10रु. से 20रु. प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अरहर और मूंग की दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। रिफाइंड और सरसों तेल के डिब्बे पर भी सीधे 15रु. से 20रु. प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।

### क्यों लगी है बाजार में आग?

**इथेनॉल पॉलिसी और कम उत्पादन**

इस बार देश के कई बड़े हिस्सों में मौसम की बेरुखी से गन्ने और दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही, गन्ने और अनाज का एक बड़ा हिस्सा 'इथेनॉल ईंधन' (पेट्रोल मिक्सिंग) के लिए डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे खाने वाले सामानों की सप्लाई कम हो गई है।

**त्योहारी मांग और जमाखोरी**

रक्षाबंधन और आने वाले गणेश उत्सव के चलते बाजार में राशन की मांग अचानक बढ़ गई है। कुछ बड़े थोक कारोबारियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए जमाखोरी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

**महंगा ट्रांसपोर्टेशन**

डीजल की ऊंची कीमतों और मानसून में सड़कों की खराबी के कारण बाहर से आने वाली गाड़ियों का मालभाड़ा बढ़ गया है। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं, दीपावली तक झेलनी होगी मारबाजार के बड़े विशेषज्ञों और थोक व्यापारियों के मुताबिक, इस महंगाई से फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि, सरकार ने घरेलू बाजार में सप्लाई सुधारने के लिए कच्चे शक्कर के आयात नियमों में ढील दी है, लेकिन इस फैसले का असर आम जनता की गली-मोहल्ले की दुकानों तक पहुंचने में कम से कम दो से तीन महीने का समय लगेगा। यानी साफ है कि दीपावली तक रायपुर की जनता को अपनी जेब और ढीली करनी ही पड़ेगी।

पहले 4,000रु. में पूरे महीने का किराना और हरी सब्जियां आ जाती थीं। अब 6,000रु. देने के बाद भी सामान कम पड़ रहा है। शक्कर और तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम इस तरह बढ़ेंगे तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार खाएगा क्या?

**मीना सोनवानी, गृहणी, पेंशन बाड़ा, रायपुर।**

### तब और अब (Price Comparison Index)

| सामग्री (प्रति किलो) | एक महीने पहले का दाम (जुलाई) | आज का ताज़ा दाम (अगस्त 2026) | सीधे जेब पर असर |
|---|---|---|---|
| शक्कर (Sugar) | ₹40 से ₹45 | ₹60 से ₹65 | ₹20 प्रति किलो सीधा महंगा |
| प्याज (Onion) | ₹30 से ₹35 | ₹50 से ₹55 | ₹20 प्रति किलो की बढ़त |
| आलू (Potato) | ₹22 से ₹25 | ₹35 | ₹10 से ₹13 महंगा |
| टमाटर (Tomato) | ₹25 से ₹30 | ₹40 से ₹50 | ₹15 से ₹20 की तेजी |
| हरी मिर्च (Green Chilli) | ₹60 | ₹100 | ₹40 प्रति किलो का बड़ा उछाल |
| धनिया पत्ती (Coriander) | [illegible] | [illegible] | सीधे ₹70 प्रति किलो की तेजी |

# मेकाहारा को है ईलाज की जरुरत!

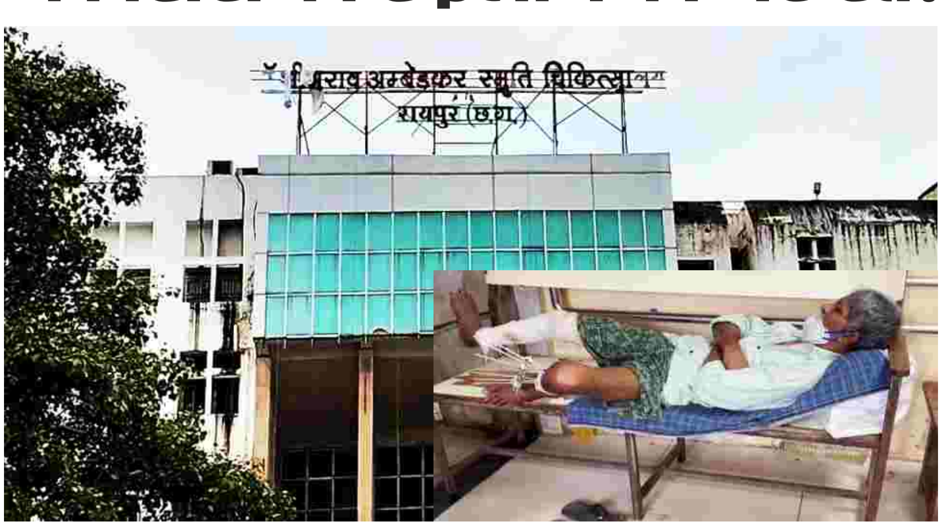


### व्हीलचेयर नहीं, जमीन पर घिसटता घायल

रायपुर | अम्बेडकर अस्पताल परिसर में इंसानियत दम तोड़ती नजर आई. एक घायल युवक, जिसके पैर पर पूरी तरह पट्टी बंधी थी, वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर घिसट-घिसट कर चलने को मजबूर था. पीड़ित ने रोते हुए बताया, "मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए अस्पताल वाले मुझे भर्ती नहीं करते और भगा देते हैं. बैठने के लिए व्हीलचेयर तक नहीं देते, मैं इसी तरह घिसटते हुए सड़क पर रहता हूँ." क्या गरीब होना इस शहर में गुनाह है?

### ...और टेबल पर लेटे रहे बुजुर्ग मरीज

अस्पताल के वार्ड के भीतर संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो गईं. एक बुजुर्ग मरीज, जिनके पैर में लोहे का रॉड लगा हुआ था और वे गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें अस्पताल प्रबंधन एक बेड तक नसीब नहीं करा पाया. वे बुजुर्ग मरीज एक छोटे और कड़े टेबल पर लेटे हुए दर्द से तड़प रहे थे. जिस उम्र में सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उस उम्र में सिस्टम ने उन्हें टेबल पर लावारिस छोड़ दिया.

### सिर पर लटकती मौत, कभी भी गिर सकती है सीलिंग

मरीजों के इस दर्द के बीच, अस्पताल की इमारत खुद एक बड़े हादसे का इंतजार कर रही है. अस्पताल के अंदर की पूरी फॉल सीलिंग जगह-जगह से बुरी तरह टूटी हुई है और नीचे लटक रही है. इलाज कराने आए मरीजों और डॉक्टरों के सिर पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है. यह भारी सीलिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है.

### खबर का असर

**'मराव' से फिर सम्मान के साथ 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर' अस्पताल बना**

पिछली बार ठीहा छत्तीसगढ़ न्यूज़ ने अस्पताल के मुख्य गेट पर टूटे लोहे के बोर्ड की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां शुरुआती शब्द गायब होने से महापुरुष के नाम की जगह 'मराव अम्बेडकर अस्पताल' पढ़ा जा रहा था. हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है. प्रशासन ने तुरंत जागकर वहां सम्मान के साथ नया बोर्ड लगा दिया है.

# आत्मानंद स्कूल का कैसा आनंद ?

## मुफ़्त पढ़ाई के नाम पर वसूली और जर्जर व्यवस्था की जमीनी कहानी

**विशेष रिपोर्ट**| छत्तीसगढ़ के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी और मुफ़्त शिक्षा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना' की शुरुआत की थी। मकसद बहुत साफ था कि पैसों की कमी के कारण किसी गरीब का बच्चा पीछे न छूटे। पिछली सरकार के समय इस योजना को जनता ने काफी पसंद किया और आज पूरे प्रदेश में 750 से भी ज्यादा आत्मानंद स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा सरकार के समय यह इतनी बड़ी योजना जमीनी हकीकत में कुछ और ही बयां कर रही है। ठीहा छत्तीसगढ़ न्यूज़ की टीम ने जब रायपुर के आत्मानंद स्कूलों का जायजा लिया, तो वहाँ बदहाली और मनमानी का एक अनोखा खेल देखने को मिला।

### सरकारी फीस ₹550, वसूली ₹2500 तक!

नियम के मुताबिक, आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सरकारी फीस केवल ₹500 से ₹550 तय की गई है। लेकिन रायपुर के एक स्कूल में बच्चों से ₹2000, ₹2200 और ₹2500 तक वसूले जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बच्चों ने बताया कि इस मोटी रकम के बदले उन्हें कोई सरकारी रसीद या पर्ची तक नहीं दी जा रही है। जब हमारी टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल राकेश गुप्ता से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने एक रफ कॉपी का पन्ना दिखा दिया, जिस पर बिना किसी सरकारी सील या साइन के हाथ से लाखों रुपयों का हिसाब लिखा हुआ था।

राकेश गुप्ता

**बच्चे तोड़फोड़ करते हैं इसलिए एडवांस पैसा:** जब प्रिंसिपल सुबूतों के सामने घिरे, तो उन्होंने एक अजीब दलील दी। प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे स्कूल में तोड़फोड़ करते हैं, इसलिए शाला विकास समिति (SMDC) के फैसले से यह 'विकास शुल्क' एडवांस में लिया जा रहा है। प्रिंसिपल ने कैमरे पर यह भी माना कि जो बच्चे किस्तों में ₹500 या ₹600 दे रहे हैं, उन्हें तब तक रसीद नहीं मिलेगी जब तक वे पूरा पैसा जमा नहीं कर देते। अब सवाल यह है कि बिना रसीद के लिया जा रहा यह नकद पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है?

सतीश

**दूसरे प्रिंसिपलों ने खोली पोल:** इस मामले पर जब ठीहा छत्तीसगढ़ न्यूज़ ने फाफाडीह चौक के पास स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (SAGES शाहिद स्मारक उत्कृष्ट विद्यालय) के वर्तमान प्रिंसिपल सतीश कुमार गौर से बात की तो इस मनमानी की पूरी पोल खुल गई। दूसरे प्रिंसिपलों ने साफ कहा, "हमारे यहाँ ऐसी कोई अनिवार्य फीस नहीं ली जा रही है। अगर समिति की बैठक में कोई बात होती भी है, तो वह पेरेंट्स की मर्जी पर होती है। किसी भी बच्चे पर पैसे देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।" इससे साफ है कि यह कोई सरकारी नियम नहीं, बल्कि सिर्फ इसी स्कूल की अपनी मनमानी है।

**आर. डी. तिवारी स्कूल की जर्जर हालत**: बात सिर्फ पैसों की नहीं है, आत्मानंद स्कूलों की हालत भी खराब हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रायपुर का आर. डी. तिवारी आत्मानंद स्कूल है। बाहर से तो इसका बोर्ड बहुत चमचमाता है, लेकिन अंदर से इस स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर और बदहाल हो चुकी है। दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है और छतें टपक रही हैं। मासूम बच्चे इस असुरक्षित भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

### टुटा स्कूल मेंटेनेंस का बजट हुआ कम

स्कूलों की इस बदहाली के पीछे बजट की कमी भी एक बड़ी वजह है। पहले आत्मानंद स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए ₹5 लाख तक की सालाना राशि आती थी, लेकिन अब यह सरकारी बजट घटकर केवल ₹1.5 लाख रह गया है। बजट में हुई इस भारी कटौती के कारण स्कूलों की साफ-सफाई, बिजली बिल और मरम्मत का काम पूरी तरह ठप पड़ गया है। एक तरफ जर्जर भवनों का खतरा और दूसरी तरफ जबरन वसूली की मार-आखिर ऐसे माहौल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे?

### योजना एक, स्कूल एक, फिर नियम अलग-अलग क्यों?

इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जब पूरे छत्तीसगढ़ में योजना एक है, स्कूलों का ढांचा एक है और सरकार का मकसद भी एक ही है, तो फिर अलग-अलग आत्मानंद स्कूलों में नियम अलग-अलग क्यों हैं? एक तरफ कुछ स्कूल इस अतिरिक्त फीस को लेने से साफ इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, कुछ स्कूल इसे अपना हक मानकर स्वीकार कर रहे हैं और बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। अगर यह सरकारी नियम है, तो सब जगह क्यों नहीं? और अगर नियम नहीं है, तो एक अकेले स्कूल को गरीब बच्चों की जेब काटने की खुली छूट किसने दी? शाला विकास समिति (SMDC) के नाम पर चल रहा यह दोहरा मापदंड आखिर कब बंद होगा?

# रायपुर की सड़कों पर आवारा मवेशी: कागज की योजना या जमीन पर समाधान ?

रायपुर। राजधानी की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा अब भी बना हुआ है। सड़क पर बैठे गाय-बैलों से यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है, खासकर रात के समय।

सरकार ने बेसहारा मवेशियों के लिए गौधाम (सुरभि गौधाम) योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में मौजूदा गोठानों को विकसित कर आधुनिक गौधाम तैयार करने और मवेशियों के चारे-रखरखाव की व्यवस्था का प्रावधान है। नगर निगम भी समय-समय पर मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है।

अब सवाल उठ रहा है कि योजनाओं और कार्रवाई के बावजूद मवेशी सड़कों पर क्यों लौट रहे हैं? स्थायी समाधान के लिए गौधामों के प्रभावी संचालन, नियमित निगरानी, पशुओं की पहचान और पशु मालिकों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।

आवारा मवेशियों की समस्या केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं है। पशुओं को खुला छोड़ने वाले मालिकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए। जनता का सवाल साफ है - योजना का असर कागज पर नहीं, रायपुर की सड़कों पर दिखाई देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए गौधाम योजना (सुरभि गौधाम) जैसी पहल शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 10 मौजूदा गोठानों को विकसित कर कुल 1,460 आधुनिक गौधाम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें शहरी क्षेत्रों के गोठान और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास की सुविधाएं भी शामिल हैं।

सरकार के अनुसार गौधामों के संचालन की जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों, पंजीकृत गौशालाओं, ट्रस्टों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से निभाई जानी है। मवेशियों के चारे और रखरखाव के लिए प्रति पशु प्रतिदिन आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन सवाल यही है कि जब योजनाएं और व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो रायपुर की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा आखिर कब खत्म होगा?

**प्रमोद दूबे**
पूर्व महापौर

नगर निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद् बैठी है ,तब से रायपुर का नाम गायपुर हो गया है। सड़को, गार्डन, कालोनियों में जंहा देखोगे वहां पर गाय बैठी रहती है शहर के आबादी को देखते हुए कम से कम 10 कांजी हाऊस बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को शहर के आसपास में 50-100 एकड़ में गौअभ्यारण्य बनाना चाहिए। आदमी गाय का दूध निकालकर गायो को सड़को पर छोड़ देता है ये जो चीजे है बड़ी अप्रिय स्थिति हो गई है रायपुर शहर की इसमे ठोस कारवाई होनी चाहिए।

**मीनल चौबे, महापौर**
नगर निगम रायपुर

सड़कों पर मवेशी क्यों हैं? गौठानों में क्या व्यवस्था है? मवेशी मालिकों पर क्या कारवाई ? अधिकारीयों को हर 15 दिन में गोठानों का फील्ड इंस्पेक्शन करने और फोटो-वीडियो के साथ सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। मवेशी मालिकों की लापरवाही से पशु सड़कों पर हैं। मालिकों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम नया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा। संस्थाओं के साथ बैठक कर नए गोठान बनाने और पुराने बिल व रजिस्टरों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।

# कार्रवाई की जद में आबकारी, पुलिस और शिक्षा मिशन के अधिकारी-कर्मचारी

• **प्रितेश बंजारे**, संवाददाता, रायपुर

रायपुर/अंबिकापुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। अलग-अलग मामलों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबन और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं कोरबा के 50 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अंबिकापुर के राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2011-12 के कथित करोड़ों रुपये के फर्नीचर घोटाले में ACB ने तत्कालीन अधिकारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

### आबकारी विभाग में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई

आबकारी विभाग से जुड़े मामलों में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है।

बताया गया है कि ACB में प्रकरण दर्ज होने के बाद आबकारी आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की। विभागीय स्तर पर भी प्रकरण से जुड़े तथ्यों और जिम्मेदारियों की जांच की जा रही है।

### निर्धारित सीमा से ज्यादा शराब बिक्री का आरोप

दूसरे मामले में आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य, जो तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बालोद से संबंधित रहे हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम अरकार, जिला बालोद में शराब जब्ती की कार्रवाई के दौरान जब्त पेटियों में रखी शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम की जांच की गई। जांच में निर्धारित बिक्री सीमा से अधिक मात्रा में थोक में शराब बेचे जाने की बात सामने आई। विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है।

उन्हें 7 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय जांच में यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो आगे और कड़ी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

### ओवर रेट शराब बिक्री पर भी नोटिस

तीसरी कार्रवाई पी. माधव राव, तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक, जिला बलौदाबाजार के खिलाफ की गई है। उनके कार्यकाल से जुड़े देशी कंपोजिट रोहासी की विदेशी शराब दुकान में निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर शराब बिक्री की शिकायत सामने आई थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

### 50 करोड़ की ठगी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम खुद कार्रवाई की जद में

उधर कोरबा जिले में करीब 50 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने दिल्ली गई पुलिस टीम पर ही कार्रवाई हो गई।

कटघोरा थाना क्षेत्र में वाहन एजेंसी संचालक से बड़ी रकम की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। मामले का मुख्य आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। साइबर थाना की मदद से आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद उसके दिल्ली में होने की पुख्ता जानकारी मिलने पर कटघोरा थाना और साइबर थाना की संयुक्त टीम दिल्ली रवाना हुई।

टीम का नेतृत्व कटघोरा थाना प्रभारी मोती पटेल कर रहे थे। टीम में विवेचना अधिकारी सहित कुल आठ पुलिसकर्मी शामिल थे।

### ट्रेन की जगह बिना अनुमति फ्लाइट से दिल्ली गए

विभागीय नियमों के अनुसार पुलिस टीम को यात्रा के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रेन से जाने की व्यवस्था करनी थी। लेकिन टीम ने अधिकारियों से अनुमति लिए बिना रायपुर से दिल्ली की यात्रा फ्लाइट से की।

मामले की एक और गंभीर बात यह सामने आई कि हवाई यात्रा का खर्च कथित तौर पर ठगी के पीड़ित वाहन एजेंसी संचालक ने उठाया था। टीम ने दिल्ली पहुंचकर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और वापस लौट आई।

बाद में इस यात्रा की जानकारी बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग को मिली। आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे विभागीय अनुशासन और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के रूप में लिया।

इसके बाद थाना प्रभारी मोती पटेल समेत टीम में शामिल सभी आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

एसपी सिद्धार्थ तिवारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने बिना अनुमति हवाई यात्रा की थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए बिलासपुर रेंज आईजी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की आगे जांच जारी है।

### 2011-12 के फर्नीचर घोटाले में ACB की बड़ी कार्रवाई

अंबिकापुर के राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2011-12 में हुई कथित करोड़ों रुपये की फर्नीचर खरीदी में अनियमितता के मामले में भी ACB ने बड़ी कार्रवाई की है।

जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ACB ने तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी एसपी पाण्डेय और दर्शन फेब्रिकेशन फर्म के प्रोपराइटर संजय पटेल समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बताया गया है कि फर्नीचर खरीदी के दौरान नियमों की अनदेखी कर आर्थिक अनियमितता किए जाने के आरोपों की लंबे समय से जांच चल रही थी। इस मामले में विभाग के करीब 6 से 7 अधिकारियों और फर्नीचर सप्लाई से जुड़ी करीब 12 फर्मों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई थी।

### दो महीने पहले जब्त किए गए थे दस्तावेज

ACB की टीम ने करीब दो महीने पहले राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय पहुंचकर फर्नीचर खरीदी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की थी। इस दौरान हार्ड कॉपी दस्तावेजों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए गए थे।

दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद ACB ने मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

### IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला

फर्नीचर घोटाले के मामले में आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 और 120(B) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 13(1) और 13(2)* के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

### सरकारी तंत्र में जवाबदेही का संदेश

इन अलग-अलग मामलों में हुई कार्रवाई से साफ है कि विभागीय नियमों की अनदेखी, भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। आबकारी विभाग में निलंबन और शो-कॉज नोटिस, पुलिस टीम के आठ सदस्यों का निलंबन और शिक्षा मिशन के पुराने घोटाले में ACB की गिरफ्तारी - तीनों घटनाओं में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच कार्रवाई का केंद्र बनी हुई है।

हालांकि, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस दिया गया है, उनके मामले में अंतिम दोष तय होना उनके जवाब और विभागीय जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा। वहीं ACB द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेगा।

इन कार्रवाइयों से विभागों में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पद और जिम्मेदारी चाहे किसी भी स्तर की हो, नियमों के उल्लंघन या कथित अनियमितता पर जवाबदेही तय की जाएगी।

# अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना

## मजदूरों के बच्चों के सपनों को मिल रही नई उड़ान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मजदूर परिवारों के उन बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना उम्मीद की ऐसी किरण बनकर सामने आई है, जिनके माता-पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ सकेंगे। अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल रहा है और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। यह योजना श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा शुरू की गई है। योजना की शुरुआत वर्ष 2025 में 100 बच्चों के साथ हुई थी। उस समय पांचवीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों का चयन कर उन्हें छठवीं कक्षा से प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। वर्ष 2026 में योजना का विस्तार करते हुए 200 नए बच्चों को इसमें शामिल किया गया। इस तरह पहले और दूसरे वर्ष के बच्चों को मिलाकर योजना से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या अब 300 हो गई है। राज्य के 33 जिलों से चयनित

बच्चे 19 प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रुंगटा पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय शामिल हैं। बच्चों को केवल स्कूल की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बेहतर आवासीय वातावरण, खेल, कला और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

**पढ़ाई से लेकर रहने - खाने तक का खर्च सरकार के जिम्मे**:- अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चयनित बच्चों की शिक्षा का खर्च उनके माता-पिता पर नहीं पड़ता। योजना के तहत पढ़ाई, छात्रावास, भोजन, गणवेश, किताब-कॉपी और आवश्यक शैक्षणिक सुविधाओं का खर्च मंडल द्वारा वहन किया जाता है। यानी मजदूर परिवारों को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय का खर्च उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि योजना उन परिवारों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई है, जिनके लिए अच्छे निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना आर्थिक रूप से मुश्किल था। कई अभिभावकों के लिए यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि अपने बच्चे

को बेहतर भविष्य देने का मौका है।

**मुख्यमंत्री ने बच्चों का बढ़ाया हौसला** :- 24 अगस्त को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योजना के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की, उनके अनुभव सुने और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे बड़े सपने देखें, खूब मेहनत करें और शिक्षा को अपने जीवन की सबसे मजबूत नींव बनाएं। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

कार्यक्रम में बच्चों की उपलब्धियां भी सामने आईं। किसी विद्यार्थी ने आईएएस बनने का सपना बताया तो किसी ने कहा कि योजना के माध्यम से मिले वातावरण ने उसका अंग्रेजी में बातचीत करने का आत्मविश्वास बढ़ाया है। ये अनुभव बताते हैं कि अवसर मिलने पर आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभा की राह नहीं रोक सकतीं।

**कैसे होता है चयन?**:- योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दिया जाता है। शुरुआती चरण में पांचवीं कक्षा पूरी कर छठवीं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को लक्ष्य बनाया गया है। पात्र बच्चों का चयन निर्धारित पात्रता और मेरिट के आधार पर किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजीकृत श्रमिक के पात्र प्रथम दो बच्चों को योजना का लाभ देने का प्रावधान है।

**आवेदन कब और कैसे करें?**:- शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू हुई थी। पहले अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 जुलाई 2026 किया गया। पात्र श्रमिक अपने बच्चों का आवेदन श्रम विभाग के पोर्टल, श्रमेव जयते एप, निकटतम श्रम कार्यालय या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते थे।

भविष्य के शैक्षणिक सत्रों में आवेदन की तिथियां विभाग द्वारा अलग से जारी की जाएंगी। इसलिए पात्र परिवारों को श्रम विभाग की अधिसूचना पर नजर रखनी होगी।

## सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

# 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के लिए यह गर्व और गौरव का क्षण है। जिले की शिक्षिका सुनीता यादव का चयन वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। देशभर से चयनित 48 स्कूली शिक्षकों में सुनीता यादव का नाम शामिल है। उन्हें आगामी 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी।

सुनीता यादव बरमकेला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी में पदस्थ हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके नवाचार, बच्चों को सीखने से जोड़ने के प्रयास और विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ से इस पुरस्कार के लिए उनका चयन प्रदेश के लिए भी विशेष उपलब्धि माना जा रहा है।

### शिक्षक परिवार में जन्म, शिक्षा के क्षेत्र में बनाया मुकाम

सुनीता यादव का जन्म 1 अगस्त 1975 को महासमुंद जिले के एक शिक्षक परिवार में हुआ। शिक्षा के माहौल में पली-बढ़ीं सुनीता यादव ने अंग्रेजी साहित्य में एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 2008 में शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और तब से वे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए नए प्रयोग और नवाचार करती रही हैं।

उनके लिए शिक्षण केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों को उनकी परिस्थितियों के अनुरूप सीखने के अवसर उपलब्ध कराना उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

### कोरोना काल की चुनौती को बनाया अवसर

सुनीता यादव के शिक्षकीय सफर में कोरोना महामारी का दौर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद थे और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के सामने ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बड़ी समस्या थी।

लेकिन सुनीता यादव ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग का मॉडल तैयार किया।

इसके लिए उन्होंने गांव की तीन कॉलेज जाने वाली छात्राओं सुमति पटेल, आंचल सिदार और श्वेता निषाद को वॉलंटियर के रूप में जोड़ा। सुनीता यादव ने अपनी ओर से दो लैपटॉप की व्यवस्था की और इन वॉलंटियर्स को मानदेय भी दिया।

इसके बाद गांव में बच्चों को एक जगह एकत्र कर उन्हें लैपटॉप के माध्यम से सुनीता यादव द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षणिक वीडियो और शिक्षा से जुड़े उनके नए प्रयोगों से जोड़ा गया। इस सामूहिक प्रयास ने कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह रुकने नहीं दिया।

## छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदी लिख रही हैं सशक्तिकरण की नई इबारत

एक समय था जब जांजगीर - चांपा गांव की पगडंडियों और खेतों में महिलाओं की भूमिका केवल पारंपरिक कृषि कार्यों और घर की चारदीवारी तक ही सीमित मानी जाती थी। लेकिन आज, आसमान में उड़ते ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की दूरगामी कृषि नीतियों और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं अब ग्रामीण महिलाओं के हाथों में सीधे तौर पर तकनीक की चाबी सौंप रही हैं। इसी बदलाव की एक जीती-जागती मिसाल हैं जांजगीर - चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोड़ी की रहने वाली हेमलता मनहर, जिन्हें आज उनका पूरा इलाका बड़े सम्मान के साथ 'ड्रोन दीदी' कहकर बुलाता है।

### तकनीक ने दिखाई तरक्की की नई राह

'नमो ड्रोन दीदी' योजना से जुड़कर हेमलता ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक पर किसी एक विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं है। जहां पहले खेतों में घंटों तक कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव करना किसानों के लिए एक थका देने वाला और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह काम हुआ करता था, वहीं आज हेमलता अपने ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरक और कीटनाशकों का बेहद सटीक, तेज और सुरक्षित छिड़काव कर रही हैं।

इस आधुनिक पद्धति से न केवल किसानों के श्रम और समय की भारी बचत हो रही है, बल्कि फसलों की पैदावार भी बेहतर हो रही है। इस नई जिम्मेदारी ने हेमलता को एक साधारण गृहिणी से एक कुशल तकनीकी उद्यमी में बदल दिया है।

### लाखों की आय

ड्रोन संचालन के जरिए कृषि कार्यों में पेशेवर तरीके से सहयोग देकर हेमलता सालाना 1 से 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही है। जिन हाथों में कल तक केवल घर की जिम्मेदारियां थीं, आज वे हाथ रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं। इस कमाई से वे न केवल अपने घर की आर्थिक जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा भी दिला पा रही हैं। यह आर्थिक लाभ उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है, जिससे वे गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।

### सरकारी योजनाओं से महिलाओं को मिल रहे हैं विकास के नए पंख

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए एक सुरक्षा चक्र का काम कर रही हैं। हेमलता राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' की भी लाभार्थी हैं। हेमलता मानती हैं कि जब महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके कौशल विकास के अवसर भी दिए जाते हैं, तो वे केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रदेश के विकास में अहम भागीदारी निभा सकती हैं।

### 'विष्णु भैया' के नेतृत्व में संवरते सपने

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नीतियों और योजनाओं की सराहना करते हुए हेमलता कहती हैं, "हमारे विष्णु भैया.. अपनी बहनों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। शासन की इन योजनाओं ने हम जैसी ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और अपने बंद आंखों से देखे गए सपनों को खुली आंखों से हकीकत में बदलने का अवसर दिया है।"

हेमलता मनहर की यह सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की बदलती स्थिति का उदाहरण है। आज हेमलता के हाथों में जो ड्रोन है, वह केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि वह उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता के वे पंख हैं, जिनसे वे विकास के आसमान को छू रही हैं।

# छत्तीसगढ़ के परमुख लोकपरब पोरा अऊ तीजा

• **शशिकला साहू,** संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ म पोरा अऊ तीजा खेती-किसानी अऊ परिवारिक जिनगी ले जुड़े दू बड़े लोकपरब आय। दूनों परब एक-दूसर ले जुड़े हवय अऊ भादो महीना म सिरिफ तीन दिन के अंतर म मनाये जाथे। ये साल पोरा 11 सितंबर अऊ तीजा 13 सितंबर के मनाये जाही।

## नंदिया-बइला के पूजा ले तीजा के लुगरा तक जानव एकर खास मानता

### पोरा तिहार

पोरा तिहार भादो महीना के पुन्नी के दिन मनाये जाथे। ये परब बिसेस करके किसान अऊ खेती-किसानी के परब आय। ये दिन किसान अपन बइला अऊ खेती म ओकर योगदान बर आभार जताथे।

लोक मानता हवय कि पोरा के दिन 'अन्न माता' गर्भ धारण करथे, इही दिन ले मतलब धान के बाली म दूध भराय के सुरुआत होथे। एकरे सेती ए दिन खेत म जाना अऊ खेती-किसानी के काम-कारज करना मना रहिथे।

पोरा तिहार कइसे मनाये जाथे?

**खेती के पूजा:**
पोरा ले एक दिन पहिली किसान अपन खेत म जाके 'गर्भ पूजा' करथें। मानता हवय कि ए पूजा ले फसल म बरकत आथे अऊ अन्न माता के किरपा बने रहिथे।

**बइला के सिंगार:**
पोरा के दिन बिहनिया बइला मन ला नहवाय जाथे। ओकर सिंग ला रंगाय जाथे अऊ घुंघरू, कौड़ी के गहना, फूल के माला अऊ दूसर साज-सिंगार ले सजाये जाथे।

**बइला के पूजा:**
ए दिन बइला मन ले कोनो काम नइ करवाय जाये। ओमन ला बढ़िया खाना खवाये जाथे। घर के महतारी-बहिनी मन बइला के पूजा करथें अऊ सुख-समृद्धि के कामना करथें।

**नंदिया-बइला अऊ चुकी-पोरा:**
पोरा तिहार म माटी ले बने नंदिया-बइला अऊ छोटे-छोटे बरतन, जेन ला 'चुकी-पोरा' कहिथें, के खास महत्व रहिथे। लइका मन ए माटी के खेलउना ले खेलथें। गांव म बइला दउड़ के आयोजन घलो होथे।

**छत्तीसगढ़िया पकवान:**
पोरा तिहार के दिन घर म छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान बनाय जाथे। ठेठरी, खुरमी, गुरहा चीला, बरा, सोहारी जइसन पकवान बनाके देवी-देवता ला भोग लगाए जाथे अऊ परसाद के रूप म बांटे जाथे।

### तीजा तिहार

तीजा तिहार पोरा के 3 दिन बाद, भादो महीना के सुक्ल पच्छ के तीज तिथि म मनाये जाथे। ये साल तीजा 13 सितंबर के मनाये जाही।

तीजा छत्तीसगढ़ के महतारी-बहिनी मन के सबले बड़े परब म गिनाये जाथे। बिहाता महतारी-बहिनी अपन पति के लंबा उमर अऊ अखंड सुहाग बर निरजला उपास रथें। कुंवारी नोनी मन सुग्घर वर मिलय, ए मनोकामना ले तीजा के उपास रखथें।

### तीजा के मानता

लोकमानता हावय कि माता पारबती (पार्वती) ह मन-ही-मन भगवान शंकर ला अपन पति रहिन। फेर राजा हिमालय अपन बेटी पारबती के बिहाव भगवान बिसनु (विष्णु) ले करवाना चाहत रिहिन। ए बात ला माता पारबती अपन सखी मन ला बताइन। सखी मन ओला घनघोर जंगल म ले गइन, जिहां माता पारबती भगवान शंकर ला पाय बर कठोर तपस्या करिन।

माता पारबती रेती के शिवलिंग बना के बिना अन्न-जल गरहण करे तपस्या करिन। भादो सुक्ल पच्छ के तीज के दिन भगवान शंकर ओकर तपस्या ले परसन होके ओमन ला अपन पत्नी के रूप म स्वीकार करिन। इही मानता के चलते महतारी-बहिनी मन अपन पति के लंबा उमर अऊ सुहाग के कामना ले तीजा के निरजला उपास रखथें।

### तीजा के लुगरा

तीजा के पूजा म नवा लुगरा अऊ सुहाग के सिंगार के खास महत्व हवय। परंपरा हावय कि तीजा के लुगरा मईके पच्छ ले दे जाथे। ए लुगरा ला मईके के मया, दुलार अऊ जिनगी भर के आसीस के परतीक माने जाथे।

### करू भात के परंपरा

तीजा के उपास के एक दिन पहिली 'करू भात' खाय के परंपरा हवय। महतारी-बहिनी मन करेला के साग अऊ भात खाथें। कम-से-कम तीन अलग-अलग घर, परोसी या परिवार के घर जाके करू भात खाय के रिवाज घलो हवय। करेला के तासीर ठंडा माने जाथे। मानता हवय कि ये उपास के बेरा पियास अऊ पित्त ला काबू म रखे म मदद करथे। एकर संग एक भावनात्मक मानता घलो जुड़े हवय- जइसे करेला म कड़वाहट होथे, वइसनेच जिनगी म आवत कठिनाई अऊ कड़वा सच्चाई ला हंसत-हंसत स्वीकार करके रिस्ता-नाता ला बनाये रखना चाही।

### गणेश चतुरथी म फरहार

तीजा के निरजला उपास के दूसर दिन गणेश चतुरथी होथे। ए दिन बिहनिया नहा-धोके महतारी-बहिनी मन शंकर-पारबती के पूजा करथें। ठेठरी, खुरमी, कतरा अऊ दूसर पारंपरिक पकवान के भोग लगाय जाथे।

पूजा के बाद 24 घंटा के निरजला उपास पूरा करके महतारी-बहिनी मन फरहार ले बरत खोलथें। तीखुर, सिंघाड़ा, साबूदाना, कतरा अऊ मौसमी फल खाये जाथे। एकर बाद घर के बड़े-सियान मन के आसीरबाद लेथें अऊ तीजा के परब पूरा होथे।

पोरा तिहार म खेती अऊ बइला के आभार हवय, त तीजा तिहार म सुहाग, परिवार अऊ मईके के मया के भाव। ए दूनों परब छत्तीसगढ़ के लोकजीवन, परंपरा अऊ संस्कृति ला आज घलो जिंदा रखे हवय।

---

# कमरछठ उपास : महतारी के ममता, परंपरा अउ बिस्वास

• **चंचल द्विवेदी,** संवाददाता, रायपुर

का आपमन कभू बिचार करे हव कि कमरछठ के दिन महतारी मन हल ले जुड़े जिनिस मन ले दूर काबर रहिथें? आखिर का वजह हरे कि संतान के लंबा उमर, अच्छा स्वास्थ अउ घर के सुख-समृद्धि के कामना ले जुड़े ए उपास म पसेर चउर अउ किसम-किसम के भाजी के महत्व बढ़ जाथे?

ए बछर कमरछठ के परब 2 सितंबर 2026, बुधवार के दिन मनाए जाही, भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि म मनाए जाने वाला ए तिहर ला कई जगह हरछठ अउ हलछठ के नाम ले घलो जाने जाथे, जबकि हमर छत्तीसगढ़ म ये कमरछठ के नाम ले परसिद्ध हे।

कमरछठ मूल रूप ले षष्ठी माता के ब्रत हरे, ए दिन दाई मन अपन संतान के लंबा उमर, अच्छा सेहत अउ सुख-समृद्धि के कामना बर उपास रथें, नवा बिहाय माईलोगिन मन संतान प्राप्ति के कामना ले घलो ये ब्रत ल रखथें।

कमरछठ के संबंध भगवान बलराम ले घलो जोड़े जाथे, भगवान बलराम ला 'हलधर' कहे जाथे, काबर कि हल ओखर प्रमुख अस्त्र माने जाथे, एकरे सेती कमरछठ म हल अउ खेती-किसानी ले जुड़े परंपरा के खास महत्व हवय।

ए दिन महतारी मन बिहनिया नहा-धोके घर अउ पूजा के ठउर ला साफ करथें, माटी के सगरी बनाके पूजा के तैयारी करे जाथे, शिव-पार्वती, गणेशजी, कार्तिकेय, श्रीकृष्ण, बलरामजी अउ हलषष्ठी माता के पूजा करे जाथे, पूजा के बाद कमरछठ के कथा पढ़े-सुनें जाथे अउ संतान के सुखी अउ लंबा जीवन के कामना करे जाथे।

मान्यता हे कि हल ले खेत जोत के पैदा करे गे अनाज के सेवन ए दिन नइ करे जाथे काबर की ए दिन हल अऊ कृषि म उपयोग होये वाले जीनस मन के पुजा करे जाथे, एकरें सेती पसेर चऊर, किसम किसम के भाजी, महुआ अउ फल जइसन जिनिस मन कमरछठ के पारंपरिक भोजन म खास जगह रखथें।

कमरछठ सिरिफ एक धार्मिक परब नो हरे, बल्कि ये हर महतारी के ममता, संतान सुख अउ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आये वाला लोक परंपरा के परतीक हरय।

---

# पिछले साल की AI मूर्ति विवाद का असर इस बार पारंपरिक रूप में विराजेंगे गणपति ?

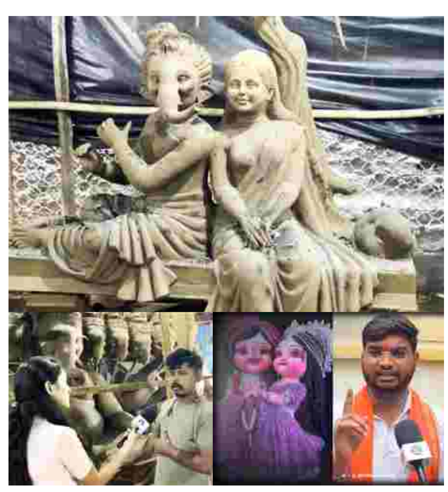

गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है, वहीं रायपुर में गणेश प्रतिमाओं को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन इस बार गणेश प्रतिमाओं की तैयारी के साथ पिछले साल का विवाद भी चर्चा में है। पिछले वर्ष रायपुर में AI और कार्टून स्टाइल में बनाई गई गणेश प्रतिमाओं को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई थी, संगठन के विरोध के बाद लाखे नगर में विराजित क्यूट बप्पा AI और कार्टून स्टाइल की प्रतिमा को ढक दिया गया था। अब देखना यह है कि पिछले साल की घटना का असर इस बार गणेश प्रतिमाओं पर कितना दिखाई देता है, इसके लिए हमारी टीम ने माना स्थित मूर्तिकारो से, उत्सव समिति और बजरंग दल से बातचीत की।

ग्राउंड पर गणेश प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों से बातचीत में सामने आया कि इस बार वे पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकारों के मुताबिक मिट्टी, पैरा और अन्य रंग रोगन की सामग्री खरीदकर मूर्ति बनाने की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है और अधिकतम मूर्तियाँ बुक हो चुकी हैं , पिछले साल की AI मूर्ति विवाद के बाद इस बार किसी गणेश स्थापना समिति की ओर से AI या कार्टून स्टाइल की प्रतिमा बनाने की मांग नहीं आई है। इसलिए मूर्तिकार चार हाथ, लंबोदर स्वरूप, बड़े कान और सूंड वाले पारंपरिक गणेश जी की प्रतिमाएं ही तैयार कर रहे हैं।

वहीं छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने गणेश चतुर्थी से डेढ़ महीने पहले गणेश प्रतिमाओं के स्वरूप का मुद्दा उठाया था और रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, समितियों और मूर्तिकारों को भगवान गणेश के वर्णित स्वरूप के मुताबिक मूर्ति निर्माण कराने की अपील की थी और साथ ही कहा अगर इस बार भी AI, कार्टून या किसी फिल्मी कैरेक्टर पर आधारित गणेश प्रतिमाएं बनाई या स्थापित की जाती हैं, तो ऐसी प्रतिमाओं के खिलाफ पिछले साल की तरह ही पुरजोर विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें ढक दिया जाएगा। साथ ही धार्मिक भावना आहत होने पर क़ानूनी कार्यवाही की भी बात की गयी है।

गणेश स्थापना समितियों का कहना है कि पिछले साल हुए विरोध को देखते हुए इस बार वे इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। समितियां पारंपरिक स्वरूप वाली गणेश प्रतिमाओं को ही स्थापित करने की तैयारी में हैं।

यानी इस बार रायपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन पिछले साल के विवाद के बाद इस बार समितियां और मूर्तिकार पारंपरिक स्वरूप को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि इस बार रायपुर में गणेश जी की AI या कार्टून स्टाइल वाली मूर्तियां शायद ही देखने को मिलें।

# डिजिटल से प्रिंट तक.. ठीहा छत्तीसगढ़ की शानदार दस्तक

**ठीहा छत्तीसगढ़** के **पाक्षिक अखबार** के प्रथम अंक ने प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान बनाई। **मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय** ने अखबार का विमोचन किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष **डॉ. रमन सिंह** और **पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल** सहित कई लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सुरता के पुरखा

# हास्य के टाइगर पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे की अनसुनी यादें

## शशि दुबे जी से विशेष बातचीत

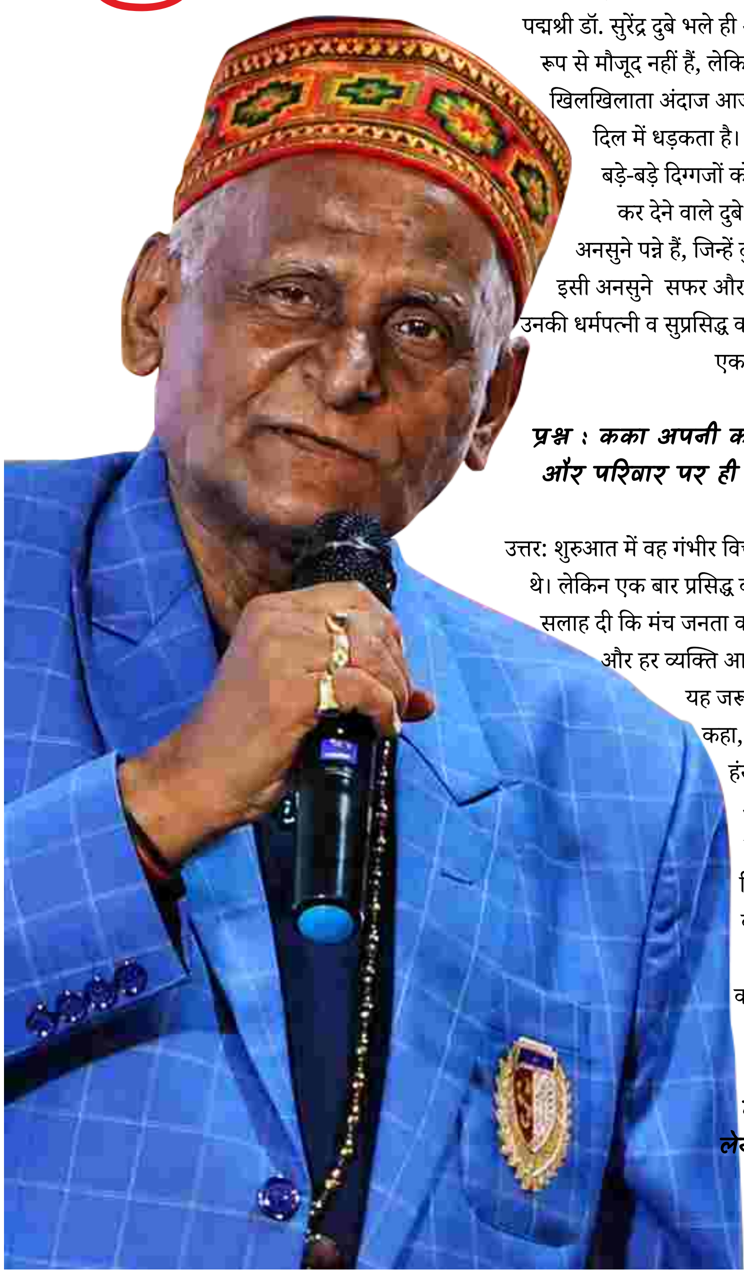

छत्तीसगढ़ की माटी के गौरव, मशहूर हास्य कवि और पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका खिलखिलाता अंदाज आज भी हर छत्तीसगढ़िया के दिल में धड़कता है। एक आम इंसान से लेकर बड़े-बड़े दिग्गजों को अपनी बातों से लोटपोट कर देने वाले दुबे जी के जीवन के कई ऐसे अनसुने पन्ने हैं, जिन्हें दुनिया नहीं जानती। उनके इसी अनसुने सफर और दिलचस्प यादों को लेकर उनकी धर्मपत्नी व सुप्रसिद्ध कवयित्री शशि दुबे ने हमसे एक बेहद खास बातचीत की।

***प्रश्न : कका अपनी कविताओं में खुद पर और परिवार पर ही सबसे ज्यादा व्यंग्य क्यों करते थे?***

उत्तर: शुरुआत में वह गंभीर विचारप्रधान कविताएं सुनाते थे। लेकिन एक बार प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि मंच जनता को हंसाने के लिए होता है, और हर व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो यह जरूरी नहीं। उन्होंने दुबे जी से कहा, "जैसे मैं अपनी पत्नी पर हंसता हूँ, वैसे ही तुम खुद पर और परिवार पर हंसो ताकि लोग बस खुलकर हँसें और किसी को बुरा भी न लगे।" बस, इसके बाद उन्होंने खुद पर और मुझ पर मजेदार कविताएं लिखनी शुरू कर दीं।

***प्रश्न : उनकी प्रसिद्ध टैगलाइन "टेंशन मत लेना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है" कैसे बनी?***

उत्तर: यह बहुत ही मजेदार किस्सा है। दरअसल,

राजस्थान के एक कवि सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया था। किसी ने गलतफहमी में हमारे छत्तीसगढ़ वाले दुबे जी की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह फैला दी। उस समय मैं दिल्ली में थी और सुबह से लगातार सहेलियों के रोते हुए फोन आ रहे थे। जब दुबे जी को इस अफवाह का पता चला, तो उन्होंने हंसते हुए मुझे फोन किया और मजाकिया अंदाज में कहा, "तुम टेंशन मत लेना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है!" बाद में यही उनकी पहचान बन गई।

***प्रश्न : क्या कॉलेज के दिनों में भी वह अपनी कविताओं से पैसे कमाते थे? उनकी पहली पॉकेट मनी क्या थी?***

उत्तर: हाँ, कॉलेज के दिनों से ही उन्हें जहाँ 5 लोग दिखते, वह कविता सुनाना शुरू कर देते थे। उन दिनों जब वह कॉलेज में पढ़ते थे, तब छोटे-छोटे गणेश उत्सव या दुर्गोत्सव के मंचों पर काव्य पाठ करने जाते थे। वहाँ उन्हें इनाम या पारिश्रमिक के रूप में 11रु. मिलते थे। उस जमाने में कॉलेज के छात्र के लिए 11रु. बहुत बड़ी रकम होती थी और यही उनकी पहली पॉकेट मनी हुआ करती थी।

***प्रश्न : वह अपनी शारीरिक दिक्कतों या बीमारियों को भी मजाक में कैसे उड़ा देते थे?***

उत्तर: वह हर बात को मजाक में लेने के आदी थे। एक बार उनका दांत टूट रहा था, तो किसी ने पूछा कि काका आपका दांत टूट रहा है क्या? इस पर उन्होंने तुरंत हंसकर कहा, "नहीं, अभी तो मैं ग्राइप वाटर पी रहा हूँ, अब नए दांत उगना चालू हो रहे हैं!" इसी तरह जब उनके घुटनों में दर्द था और वह थोड़ा झुककर चलते थे, तो लोग पूछते थे कि काका झुककर क्यों चल रहे हो? वह कहते थे, "यह मेरा घुटने का दर्द नहीं, यह मेरी स्टाइल है, मैं देवानंद स्टाइल में चलता हूँ।" वह अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसी में निपटा देते थे।

***प्रश्न : उनकी प्रसिद्ध कविता 'बस्तर' की रचना कैसे हुई और इसे पहली बार कहाँ सुनाया गया था?***

उत्तर: दुबे जी को बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के माहौल से बहुत गहरा लगाव था। वह मानते थे कि बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बन सकता है। इसी प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने 'बस्तर' पर एक बेहद खूबसूरत कविता लिखी थी। इस कविता को उन्होंने पहली बार रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पर सुनाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया।

***प्रश्न : दुबे जी की 'भाई बांटा' और 'लौट आओ बेटे राजू' जैसी गंभीर कविताओं के पीछे क्या संदेश था?***

उत्तर: साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था, तब उन्होंने उस बड़ी सामाजिक परिस्थिति को 'भाई बांटा' नाम देकर हास्य में ढाल दिया, जिसे जनता ने खूब पसंद किया। वहीं दूसरी ओर, 'लौट आओ बेटे राजू' वृद्ध माता-पिता के अकेलेपन और घर छोड़कर जाने वाले बच्चों के दर्द पर आधारित एक बेहद भावुक कविता थी। इसे सुनकर मंच के सामने बैठे हजारों लोगों की आँखों में आँसू आ जाते थे।

# छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स

## साध्य PSC एकेडमी

**प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है?**

(A) न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद (B) शत्रुघ्न सिंह

(C) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (D) मोहन पवार

सही उत्तर: (C) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस विशेषज्ञ समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम. के. राऊ, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया है।

**प्रश्न 2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम में चयनित होकर रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है?**

(A) बिलासपुर (B) दुर्ग (C) रायपुर (D) राजनांदगांव

सही उत्तर: (D) राजनांदगांव

व्याख्या: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की अंतरराष्ट्रीय महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने महिला 53 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम (स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम) वजन उठाकर रजत पदक (सिल्वर मेडल) हासिल किया और स्नैच राउंड में 88 किलोग्राम भार उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया।

**प्रश्न 3: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पहली 'खुली जेल' (Open Jail) को ₹23 करोड़ की लागत से किस जिले के 'पथरा' गांव में शुरू करने की मंजूरी दी है?**

(A) बेमतरा (B) दंतेवाड़ा (C) महासमुंद (D) सरगुजा

सही उत्तर: (A) बेमतरा

व्याख्या: राज्य सरकार ने बेमतरा जिले के पथरा गांव में छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल (ओपन जेल) विकसित करने का आदेश जारी किया है। इसके शुरुआती चरण में जेल में अच्छे आचरण वाले 200 आजीवन कारावास के कैदियों को रखा जाएगा, जहाँ उन्हें अपने परिवार के साथ रहने तथा कृषि व पशुपालन के माध्यम से समाज में पुनर्वास के अवसर दिए जाएंगे।

**प्रश्न 4: हाल ही में जून 2026 में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई जी का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था?**

(A) 1988 (B) 2003 (C) 2019 (D) 1995

सही उत्तर: (C) 2019

व्याख्या: छत्तीसगढ़ की महान पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई जी का 5 जून 2026 को एम्स में निधन हो गया। उन्हें लोक संस्कृति में उनके अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से अलंकृत किया गया था।

**प्रश्न 5: 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026' के तहत किसी नाबालिग, महिला या सामूहिक रूप से जबरन मंतारण (धर्म परिवर्तन) कराने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है?**

(A) 7 से 10 साल की जेल (B) आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 25 लाख रुपये का जुर्माना (C) 5 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना (D) 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना

सही उत्तर: (B) आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 25 लाख रुपये का जुर्माना

व्याख्या: पुराने 1968 के कानून की जगह 10 जुलाई 2026 से नया 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026' प्रभावी हो गया है। इसके तहत पैसे के लालच या धोखे से मंतारण करने पर 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान है, लेकिन यदि मंतारण किसी नाबालिग, महिला का हो या सामूहिक रूप से किया गया हो, तो आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के भारी जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

**प्रश्न 6: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में छत्तीसगढ़ की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के तहत 'रजत कमल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है?**

(A) जोगीमारा (B) अबूझमाड़ (C) रामनामी (D) महानदी

सही उत्तर: (C) रामनामी

व्याख्या: भारत बाला गणपति द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म "रामनामी" को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंतर्गत 'रजत कमल पुरस्कार' प्रदान किया गया है। यह फिल्म जांजगीर-चांपा क्षेत्र में मुख्य रूप से संकेंद्रित रामनामी समुदाय की अनूठी संस्कृति और उनके पूरे शरीर पर राम-राम गोदवाने की अटूट आस्था को दर्शाती है।

**प्रश्न 7: वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) समाप्त होने के बाद, देश के किस पूर्व सुरक्षा कैंप को स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र' (प्रथम जन सुविधा केंद्र) के रूप में स्थापित किया गया है?**

(A) गीदम कैंप (दंतेवाड़ा) (B) कुनकुरी कैंप (जशपुर) (C) गरियाबंद कैंप (D) नेतानार कैंप, जगदलपुर (बस्तर)

सही उत्तर: (D) नेतानार कैंप, जगदलपुर (बस्तर)

व्याख्या: मार्च-अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर शून्य होने के बाद खाली हुए कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। इसी पहल के तहत बस्तर के जगदलपुर में स्थित 'नेतानार कैंप' देश का पहला ऐसा सुरक्षा कैंप बना है, जिसे 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र' नामक जन सुविधा केंद्र के रूप में स्थानीय समुदाय के लिए समर्पित किया गया है।

**प्रश्न 8: छत्तीसगढ़ के किस जिले के 'ग्राम बाबा मोहतरा' के तालाब में ग्रामीणों के साथ करीब 175 वर्षों तक रहने वाले मगरमच्छ 'गंगाराम' की कहानी को एनसीईआरटी (NCERT) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा?**

(A) बेमतरा (B) नारायणपुर (C) गरियाबंद (D) जसपुर

सही उत्तर: (A) बेमतरा

व्याख्या: बेमतरा जिले के ग्राम बाबा मोहतरा के एक तालाब में रहने वाले मगरमच्छ 'गंगाराम' और ग्रामीणों के बीच इंसान व वन्यजीव के अनूठे रिश्ते की कहानी को एनसीईआरटी (NCERT) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2019 में इस मगरमच्छ की मृत्यु होने पर पूरे गांव ने शोक मनाया था तथा रीति-रिवाजों के साथ अंतिम विदाई देकर तालाब के पास उसकी एक भव्य प्रतिमा और स्मारक भी बनवाया है।

**प्रश्न 9: छत्तीसगढ़ राज्य की पहली 'राजकीय तितली' का चुनाव करने के लिए वन विभाग की विशेषज्ञ समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई तीन प्रजातियों की दौड़ में कौन सी तितली प्रजाति शामिल नहीं है?**

(A) कॉमन बैंडेड पीकॉक (Common Banded Peacock) (B) स्पॉट टेल (Spot Tail) (C) ऑरेंज ओकलीफ (Orange Oakleaf) (D) ब्लू मॉर्मन (Blue Mormon)

सही उत्तर: (D) ब्लू मॉर्मन (Blue Mormon)

व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 'राजकीय तितली' का चयन करने जा रही है। इसके लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने तीन प्रजातियों - कॉमन बैंडेड पीकॉक, स्पॉट टेल, और ऑरेंज ओकलीफ को शॉर्टलिस्ट (दौड़ में शामिल) किया है, जबकि ब्लू मॉर्मन इसमें शामिल नहीं है।

**प्रश्न 10:छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (अबूझमाड़) जिले के किन स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है?**

(A) पीला कोसरा, काला कोसरा और तीखुर (B) जस्प्योर और जसक्राफ्ट (C) हंसुली और गिलर आभूषण (D) कोसा सिल्क और वन कंद

सही उत्तर: (A) पीला कोसरा, काला कोसरा और तीखुर

व्याख्या: नारायणपुर (अबूझमाड़) के तीन प्रमुख उत्पादों - 'पीला कोसरा' (आर्क जो औषधीय गुणों से भरपूर और डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है), 'काला कोसरा' (गहरे छिलके वाला कुटकी मिलेट) और 'तीखुर' (हल्दी परिवार का कंद) को जीआई टैग (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के प्रयासों से शुरू की गई है।